



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939

No. 555]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

संख्या 58/ 2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 723(अ)--सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा: -

1. (1) ये नियम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली, 2017 कहलाएंगे।
(2) ये नियम 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,-
 - (i) नियम 2 में, खण्ड (इ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाएगा, यथा:-
'(च) "कर विजक" से तात्पर्य केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 31 में संदर्भित कर विजक से है।';
 - (ii) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्डों को शामिल किया जाएगा, यथा:-
“(खग) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), और इसके तहत बनाए गए नियम,
(खघ) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), और इसके तहत बनाए गए नियम; और”;
 - (iii) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"6. ऐसे मामले जिनमें प्रतिअदायगी की राशि या दर को निर्धारित नहीं किया गया है –

(1) (क) जहाँ किसी भी वस्तु के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी वस्तुओं का निर्यातक, नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों या इनपुट सेवाओं का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये करों को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

वशर्ते कि

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(ख) खंड (क) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण करेगा।

(2) (क) जहाँ एक निर्यातक चाहता है कि उसे अनंतिम रूप से प्रतिअदायगी दिया जाए, वह उप-नियम (1) की धारा (क) के तहत आवेदन करते समय सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास आवेदन कर सकता है कि उसको ऐसे सामानों के निर्यात पर प्रतिअदायगी की अनंतिम राशि दी जाए जब तक उस उप-नियम के खंड (ख) के तहत प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण नहीं हो जाता।

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर विचार करने के बाद, अनंतिम रूप से राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जो की निर्यातक द्वारा ऐसे निर्यात के संबंध में दावा की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती:

वशर्ते कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्यात के संबंध में प्रतिअदायगी के अनंतिम भुगतान की अनुमति देने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर सकता है कि निर्यातक को ऐसी रकम के लिए एक सामान्य बांड में प्रवेश करना होगा, और ऐसी परिस्थितियों के अधीन ही मिलेगा; या ऐसी रकम के लिए एक बांड में प्रवेश करना होगा जो की किसी विशेष खेप के संबंध में निर्यातक द्वारा दावा की गई प्रतिअदायगी की पूरी राशि से अधिक नहीं होगा और अपने आपको बाध्य करना होगा—

(i) अनंतिम रूप से स्वीकृत राशि वापस करने के लिए, यदि किसी भी कारण से यह पाया जाता है कि प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं थी; या

(ii) अधिक राशि वापसी करने के लिए, यदि कोई हो, यदि यह पाया जाता है कि प्रतिअदायगी की देय राशि ऐसे निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की जा चुकी राशि से कम थी:

वशर्ते कि जब ऐसे सामानों पर प्रतिअदायगी की देय राशि या दर का अंत में निर्धारित किया जाता है, तो इस तरह के निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की गयी राशि को अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि के खिलाफ

समायोजित किया जाएगा और यदि समायोजित राशि अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि से अधिक है या कम है, तो ऐसे निर्यातक को, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अतिरिक्त राशि चुकानी होगी या वो कमी का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बांड, ऐसी जमानत या सुरक्षा के साथ हो सकता है जैसा कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष कर सकता है।

(3) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो -

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य हेतु, "निर्यात के स्थान" का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1962 का 52) के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोई अन्य जगह जहां से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है।";

(iv) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"7. ऐसे मामले जिनमें निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर कम है -

(1) जहां किसी भी वस्तु के संबंध में, निर्यातक को पता चलता है कि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित, जैसा भी मामला हो, वस्तु की श्रेणी के लिए प्रतिअदायगी की राशि या दर, वस्तुओं के निर्माण या उत्पाद में इस्तेमाल किए गए सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किये गये शुल्क या सेवाओं पर भुगतान किये गये कर के अस्सी प्रतिशत से कम है, तो वो नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी का दावा न किया गया हो, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों या इनपुट सेवाओं का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये करों को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

वशर्ते कि -

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के

2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, निर्यातक को ऐसी निर्धारित राशि या दर जैसा कि उचित हो पर प्रतिअदायगी का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, यदि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, वास्तव में इस उप-नियम के तहत निर्धारित राशि या दर के अस्सी प्रतिशत से कम है।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनंतिम प्रतिअदायगी राशि का भुगतान किया जायेगा, और जहां निर्यातक इच्छा रखता है कि उन्हें आगे और प्रतिअदायगी अनंतिम रूप से दी जाये, वह नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में दिए गए आवेदन की विधि के अनुसार पहले से ही भुगतान किए गए अनंतिम प्रतिअदायगी के विवरण के साथ, उप-नियम (1) के तहत आवेदन करने के समय, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को आवेदन कर सकता है, और आगे और अनंतिम प्रतिअदायगी की अनुमति को इस तरीके से और उप-नियम (2) के खंड (ख) और (ग) और नियम 6 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन माना जाएगा, बशर्ते कि दावेदार द्वारा निष्पादित आवश्यक बांड केवल नियम 3 के तहत निर्धारित या नियम 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस नियम के अंतर्गत अधिकृत अनंतिम प्रतिअदायगी, के अंतर के लिये ही निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो -

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (2) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य हेतु, "निर्यात के स्थान" का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1962 का 52) के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोई अन्य जगह जहां से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है।";

(V) नियम 9 में, खंड (घ) में, -

(i) शब्द "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्दों के लिए, शब्द "सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) " या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(vi) नियम 10 में, "या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(vii) नियम 13 में, उप-नियम (2) में,-

(क) खंड (iii) में, अक्षरो और अंक "एआरई -1" के लिए, "कर विजक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(v) प्रतिअदायगी की दर के संबंध में संचार की प्रतिलिपि जहां प्रतिअदायगी का दावा इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के तहत सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित दर के लिए हो।"

(viii) नियम 15 में, उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(1) जहां किसी भी निर्यातक को पता चलता है कि उसे भुगतान की गई प्रतिअदायगी की राशि केंद्रीय सरकार या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर के आधार पर हकदार होने की तुलना में कम है तो वह अनुबंध III के फार्म में एक पूरक दावे को तरजीह दे सकता है:

बशर्ते कि निर्यातक तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे पूरक दावे को प्राथमिकता देगा -

(i) जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी की दर निर्धारित या संशोधित की गयी हो, शासकीय राजपत्र में ऐसी दर के प्रकाशन की तारीख से;

(ii) जहां प्रतिअदायगी की दर को नियम 6 या नियम 7 के तहत निर्धारित या ऊपर की ओर संशोधित की गयी हो, संबंधित व्यक्ति को उक्त दर को संप्रेषित करने की तारीख से;

(iii) अन्य सभी मामलों में, उचित अधिकारी द्वारा मूल प्रतिअदायगी के दावों के भुगतान या निपटान की तारीख से:

बशर्ते और आगे कि -

(i) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने की अवधि तक विस्तार कर सकता है और यह कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अवधि को छह महीनों तक और बढ़ा सकता है;

(ii) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता है;

(iii) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा";

(ix) नियम 16 क में, उप-नियम (4) हेतु परंतुक में, -

- I. खंड (i) में, शब्दों "या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो" का लोप किया जाएगा;
- II. खंड (ii) में शब्दों " या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो" का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 609/43/2017-डीबीके]

आनंद कुमार झा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं०. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 मई, 1995 को सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016, सा.का.नि. 1019(अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2017

No. 58/ 2017-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 93A read with section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely:-

3. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2017.

4. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,-

(v) in rule 2, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(f) “tax invoice” means the tax invoice referred to in section 31 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).’;

(vi) in rule 3, in sub-rule (1), after the clause (bb), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(bc) the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder,

(bd) the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the rules made thereunder; and”;

(vii) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

“6. Cases where amount or rate of drawback has not been determined.-

(1)(a) Where no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, any exporter of such goods may, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in terms of sub-rule (3) of rule 5, apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of drawback thereof stating all the relevant facts including the proportion in which the materials or components or input services are used in the production or manufacture of goods and the duties paid on such materials or components or the tax paid on input services:

Provided that-

(i) in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he shall apply to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one of the said places of export;

(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(iii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iv) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(b) On receipt of an application under clause (a), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, shall, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, determine the amount or rate of drawback in respect of such goods.

(2)(a) Where an exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, while making an application under clause (a) of sub-rule (1) apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods pending determination of the amount or rate of drawback under clause (b) of that sub-rule.

(b) The Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, after considering the application, allow provisionally payment of an amount not exceeding the amount claimed by the exporter in respect of such export:

Provided that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such export, require the exporter to enter into a general bond for such amount, and subject to such conditions, as he may direct; or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount claimed by such exporter as drawback in respect of a particular consignment and binding himself, -

(i) to refund the amount so allowed provisionally, if for any reason, it is found that the duty drawback was not admissible; or

(ii) to refund the excess, if any, paid to such exporter provisionally if it is found that a lower amount was payable as duty drawback:

Provided further that when the amount or rate of drawback payable on such goods is finally determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted against the drawback finally payable and if the amount so adjusted is in excess or falls short of the drawback finally payable, such exporter shall repay to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, the excess or be entitled to the deficiency, as the case may be.

(c) The bond referred to in clause (b) may be with such surety or security as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may direct.

(3) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,—

(a) revoke the rate of drawback or amount of drawback, determined under clause (b) of sub-rule (1) by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or

(b) direct the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, to withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined.

Explanation.— For the purpose of this rule, “place of export” means customs station or any other place appointed for loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has exported the goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of drawback is sought.”;

(iv) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. Cases where amount or rate of drawback determined is low.— (1) Where, in respect of any goods, the exporter finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, for the class of goods is less than eighty per cent. of the duties or taxes paid on the materials or components or input services used in the production or manufacture of the said goods, he may, except where a claim for drawback under rule 3 or rule 4 has been made, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in terms of sub-rule (3) of rule 5, make an application to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of drawback thereof stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components or input services are used in the production or manufacture of goods and the duties or taxes paid on such materials or components or input services:

Provided that -

- (i) in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he shall apply to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one of the said places of export;
- (ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (iii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iv) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, allow payment of drawback to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriate, if the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, is in fact less than eighty per cent. of such amount or rate determined under this sub-rule.

(3) Provisional drawback amount, as may be specified by the Central Government, shall be paid by the proper officer of Customs and where the exporter desires that he may be granted further drawback provisionally, he may, while making an application under sub-rule (1), apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, in this behalf in the manner as has been provided in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 for the application made under that rule along with details of provisional drawback already paid and the grant of further provisional drawback shall be considered in the manner and subject to the conditions specified in clauses (b) and (c) of sub-rule (2), and sub-rule (3) of rule 6, subject to the condition that bond required to be executed by the claimant shall only be for the difference between amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4 by the Central Government and the provisional drawback authorised by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under this rule.

(4) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,—

(a) revoke the rate of drawback or amount of drawback determined under sub-rule (2) by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or

- (b) direct the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, to withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined.

Explanation.- For the purpose of this rule, “place of export” means customs station or any other place appointed for loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has exported the goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of drawback is sought.”;

- (v) in rule 9, in clause (d),-

(A) for the words “Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise, as the case may be or the Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs”, shall be substituted;

(B) the words “or of Central Excise” shall be omitted;

- (vi) in rule 10, the words “or of Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise” shall be omitted;

- (vii) in rule 13, in sub-rule (2),-

(A) in clause (iii), for the letters and figure “ARE-1”, the words “tax invoice” shall be substituted;

(B) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) copy of communication regarding rate of drawback where the drawback claim is for a rate determined by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under rule 6 or rule 7 of these rules.”;

- (viii) in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Where any exporter finds that the amount of drawback paid to him is less than what he is entitled to on the basis of the amount or rate of drawback determined by the Central Government or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, he may prefer a supplementary claim in the form at Annexure III:

Provided that the exporter shall prefer such supplementary claim within a period of three months, -

- (i) where the rate of drawback is determined or revised under rule 3 or rule 4, as the case may be, from the date of publication of such rate in the Official Gazette;
- (ii) where the rate of drawback is determined or revised upward under rule 6 or rule 7, as the case may be, from the date of communicating the said rate to the person concerned;
- (iii) in all other cases, from the date of payment or settlement of the original drawback claim by the proper officer :

Provided further that –

- (i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months and that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand

rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.”;

(ix) in rule 16A, in the proviso to sub-rule (4),-

- (I) in clause (i), the words “or Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be” shall be omitted;
- (II) in clause (ii), the words “or Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be” shall be omitted;

[F. No. 609/43/2017-DBK]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number 39/1995-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 441 (E), dated the 26th May, 1995 and was last amended vide notification number 132/2016-Customs (N.T.), dated the 31st October, 2016 vide number G.S.R. 1019(E), dated the 31st October, 2016.